

ई.डब्ल्यु.एस. कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने अन्य पार्टियों का समर्थन पाने के लिए 12 नवम्बर को सर्वदलीय बैठक बुलाई

चेन्नई, 8 नवंबर (वार्ता)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं सत्तारूढ़ द्रविण मुनेत्र कषमम (द्रमुक) अध्यक्ष एम.के.स्टालिन ने 12 अक्टूबर को सभी विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेंक्शंस (ई.डब्ल्यु.एस.) को आरक्षण को लेकर आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी।

स्टालिन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के एक दिन बाद यह बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।

मंगलवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि, बैठक 12 नवंबर को पूर्वाह्न 10.30 बजे राज्य

रिज़ल्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है जिससे सभी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अभिभावक बार- बार स्कूलों में जाकर जानकारी लेते हैं लेकिन स्कूलों के संस्था प्रधानों से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। कक्षा पांचवीं में 14 लाख व 53 हजार और कक्षा आठवीं में 12 लाख 63 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। अंकतालिका कब तक आयेगी इसके बारे मे कोई जानकारी नहीं है। राज्य में इतना समय तो कक्षा 10 व 12वीं की अंकतालिका आने में भी नहीं लगता है। शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद का कहना है कि राज्य के लाखों विद्यार्थियों को समय पर अंकतालिका नहीं मिलना खेद का विषय है। इससे विद्यार्थियों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिक्षक संघ रेसटा की राज्य के शिक्षा मंत्री व निदेशक से मांग है कि इस मामले में तुरंत सज़ान लेते हुए स्कूलों में अंकतालिकाएं भिजवाई जाएं।

‘जो नेता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जिम्मेदारी है। अगर वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो समय किसी का गुलाम नहीं है। जब समय आएगा तो अपने आप फैसला होगा। पार्टी अब भी हर बात को नोट कर रही है। चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। गलत बयानबाजी करने वाले हर नेता की बात नोट की जा रही है। चाहे मंत्री हो या विधायक इस तरह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कुछ बोलकर पार्टी नुकसान करते हैं तो जनता और कार्यकर्ता उन्हें माफ नहीं करेंगे।”

बाल श्रम के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि, अभियुक्त मोहम्मद सय्यम उन्हें यहां लेकर आया है। बच्चों ने बताया कि, वह उनसे जबर्नत चुड़ियां बनवाने का काम करवाता है। करीब पंद्रह घंटे काम कराने के बाद भी उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा न तो उन्हें वाहर आने-जाने दिया जाता है और ना ही किसी व्यक्ति से बातचीत करने देता है। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

कांग्रेस का ट्विटर हैण्डल ब्लॉक नहीं होगा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैंगलुरु की स्थानीय अदालत के इस संबंध में दिये गये फैसले पर तत्काल रोक लगाई

बैंगलुरु, 8 नवम्बर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी और उसकी भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने वाले विशेष अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया। बैंगलुरु शहरी जिले की एक विशेष अदालत ने सोमवार को ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएससी) और इसकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ‘हैडल’ को सुनवाई की अगली तारीख तक “ब्लॉक” करने का निर्देश दिया था। हालांकि अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। बैंगलुरु शहरी जिले की एक विशेष अदालत का आदेश एमआरटी म्यूजिक द्वारा एक वाद दायर किए जाने के बाद आया था। एमआरटी म्यूजिक ‘केजीएफ चैप्टर 2’ फिल्म के ‘साउंड ट्रैक’ का कॉपीराइट धारक है। इसने अदालत में वाद दायर करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने ‘आईएनसी इंडिया’ और ‘भारत जोड़ो’ ट्विटर ‘हैडल से कुछ वीडियो ट्वीट किए थे जिनमें हिट फिल्म केजीएफ–2 के म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर साउंड रिकॉर्ड्स के अवैध इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया तो इससे म्यूजिक लेबल को नुकसान होगा

- मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि, कोर्ट के इस फैसले से 100 सालों से लड़ी जा रही लड़ाई को बहुत बड़ा आधार पहुंचा है, और इसके कारण सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचेगा।**

सचिवालय के नमक्कल कविनार मालिगई में होगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि चूंकि यह आरक्षण सामाजिक न्याय और समानता को बनाए रखने और सामाजिक न्याय की नीति के खिलाफ है, इसलिए 12 अक्टूबर को सभी विधायक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है, ताकि आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी विधायक दलों के नेताओं की बैठक के

रिज़ल्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यही इंगित किया है कि वह परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकती है। “इसके साथ ही उसने कई बार यह भी कहा है कि वह परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। अतः इस मामले में रूस की स्थ